इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। (व्यवधान) मैं यह कहूंगा कि चुनाव मई के शुरू में ही होने चाहिए। महोदय, मैंने गम्भीर आरोप लगाये हैं। यदि इन गम्भीर आरोपों से इन्कार किया जाता है तो भी बात खत्म नहीं होती है। (व्यवधान) इस मामले में विलम्ब अथवा इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जन व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामले में, तमिलनाडु में जो कुछ हुआ है उस मामले में हम सरकारी जांच की मांग करते हैं। हमें इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं मानना चाहिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को, जन व्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्या है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इस सभा को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वर्ष 1989 के उत्तरार्ध में और वर्ष 1990 में जो कुछ हुआ है, तमिलों के लिए आत्म-निरीक्षण के अनुरोध के अन्तर्गत तथा अलगाववाद के समर्थन में एक पृथक तमिलनाडु की स्थापना के अपने गुप्त उद्देश्य की प्रोत्साहन देने के लिए डी० एम० के० ने जो किया है, इन सब मामलों की सरकारी जांच की जायेगी और इनकी जांच के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की जायेगी। तमिलनाडु के लोग माननीय प्रधानमन्त्री जी से चुनाव और जांच कराये जाने की मांग का स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

3.46 म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

खाड़ी में व्याप्त स्थिति

सभापति महोदय : खाड़ी संकट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : सभापति महोदय जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि युद्ध बन्द कराने और खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये 23 फरवरी की सुरक्षा परिषद द्वारा किये गये प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ। जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है और विगत दो दिनों से जारी है। इसके परिणाम वास्तव में विनाशकारी होंगे। ईराक और कुवैत लगभग बिल्कुल नष्ट हो सकते हैं। इन दो देशों के हजारों लोगों के दुख उठाने और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाने की संभावना है। इन विनाशकारी हथियारों के उपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मानवता के विरुद्ध एक अपराध है।

सुरक्षा परिषद में जिसकी बैठक सोवियत संघ की पहल पर बुलायी गयी थी और जिसमें श्री गोर्बाचोव के प्रस्ताव पेश किये थे, भारतीय शिष्ट मंडल ने दोनों पक्षों के बीच मतान्तर दूर कराने का तथा युद्ध बन्द कराने के लिये एक आधार तैयार करने का हर संभव प्रयास किया था। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आधार रूप में एक दस्तावेज तैयार करने के हमारे परामर्श को अधिकांश सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में एक समय तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में मसौदा तैयार करने के कार्य को भारत, इक्वाडोर और अस्ट्रीया के जिम्मे सौंपने के बारे में सोचा था; दुर्भाग्यवश कुछ सदस्यों द्वारा कठोर रुख अपना लिये जाने के कारण कि वर्तमान स्थिति में सुरक्षा परिषद को कोई भूमिका नहीं निभानी है। परिषद के लिये संयुक्त राष्ट्र

के चार्टर के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करना असंभव हो गया। तब से सुरक्षा परिषद मूक बनी रही। हमने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की सरकारों से उनकी राजधानियों में सम्पर्क स्थापित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे न्यूयार्क में सुरक्षा परिषद में अपने प्रतिनिधियों को निर्देश भेजे ताकि सुरक्षा परिषद अपनी उचित भूमिका निभा सके। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच हम न्यूयार्क में सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों से, यह देखने के लिए सम्पर्क बनाये हुए है कि सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, हमारा सर्वप्रथम कार्य निर्धारित समय के अन्तर्गत कुवैत से ईराक की सम्पूर्ण वापसी के आधार पर युद्ध को बन्द कराना है। बिना और समय गंवाये सुरक्षा परिषद को इस शान्तिपूर्ण कार्य को करने का दायित्व अपने हाथों में लेना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति : आमतौर पर ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी जो कहा है वह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। सुबह हमने यह मुद्दा उठाया था और हम चाहते हैं कि जर्मनी लड़ाई शुरू हो जाने के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए सभा द्वारा एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाए। हमने विश्व समुदाय से अनुरोध करने की कोशिश की ताकि युद्ध रुक जाए। वह संकल्प अध्यक्षपीठ के पास है। इसका क्या हुआ ?

श्री चन्द्रशेखर : यह सत्य है कि इस सम्बन्ध मे एक सुझाव दिया गया था कि हमें सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए। सभा के कुछ वर्गों को इस पर कुछ आपत्ति थी।

एक माननीय सदस्य : किस वर्ग को ? **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर : लेकिन मैंने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की थी और सभी सहमत थे कि सरकार को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए। यह वक्तव्य उन्हें दिखाया गया था और सभी राजनैतिक दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के गम्भीर मुद्दे पर सभा में मतभेद नहीं होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम यह स्थिति स्वीकार करते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें जवाब दे रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय; मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो भारतीय नागरिक ईराक में फसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, ईराक में भारतीय नागरिक 107 या 109 हैं, उनको इस समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले जब उनसे कहा गया तो उस समय वे आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन चिंता ज्यादा कुवैत में है, जहां हमारे लगभग 5000 नागरिक अब भी हैं और उनमें से बहुत से लोग लड़ाई छिड़ी थी, उससे पहले उसके तुरंत बाद भी आने को तैयार

नहीं थे। आज दिक्कत यह है कि उनको निकालना बहुत कठिन है, असंभव तो मैं नहीं कह सकता फिर भी जितने लोग वहां पर उस लड़ाई में हैं, हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी सहायता वे कर सकें, करें।

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : बगदाद स्थित हमारा दूतावास किस प्रकार बद हो गया? **(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : बगदाद स्थित हमारे मिशन को बन्द कर दिया गया है। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इराक में रह रहे हमारे देश के राष्ट्रकों के संबंध में कोई व्यवस्था की गई है, क्योंकि यह कहा जा रहा है, कि इराक स्थित हमारा दूतावास बन्द कर दिया गया है।

प्रो० राम गणेश कापसे सभी राष्ट्रों के दूतावास वहां कार्य कर रहे हैं। केवल हमारा दूतावास ही बन्द किया गया है **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर : यह सत्य नहीं है कि सभी दूतावास वहां कार्य कर रहे हैं। 'दक्षेस' के सदस्य देश, खाड़ी देश या पश्चिमी जगत के किसी देश का दूतावास वहां कार्य नहीं कर रहा है। यदि मेरी जानकारी सत्य है, तो केवल दो-तीन देशों के दूतावास ही वहां कार्य कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार हम उन आखिरी तीन देशों में से है, जिन्होंने अन्त में अपना दूतावास खाली किया है। मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। केवल क्यूबा और सोवियत संघ के थोड़े बहुत कर्मचारी वहां है। हमने किसी अन्य देश के साथ कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने अपने कूटनीति कर्मचारियों से तेहरान में रहकर भारत के हितों को देखने के लिए कहा है **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : उन्हें अपने देश में वापिस लाने के लिए क्या किया जायेगा? क्या आप इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे? कुवैत में भी लगभग 4000 लोग हैं।

श्री चन्द्रशेखर : कुवैत की स्थिति के बारे में आपको पता ही होगा, उस स्थिति में लोगों को निकाल पाना असंभव है। हम इराक से लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसी युद्ध की स्थिति आज वहां बनी हुई है उसमें लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में, मैं सदन को उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के बारे में कोई आश्वासन देने में अपने को असमर्थ पाता हूं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप उनको निकालने की घोषणा करते हैं उस स्थिति में मार्ग में उनके लिए और समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में चर्चा जारी रखी जाये। अब श्री जसवन्त सिंह बोलेंगे।